



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 262]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 9, 2015/आश्विन 17, 1937

No. 262]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2015/ASVINA 17, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2015

सं. 40 / 2015-2020

विषय : एमईआईएस स्कीम के तहत आशय की घोषणा के संबंध में।

फा. सं. 01/61/180/152/एम 16/पीसी 3.—विदेश व्यापार महानिदेशालय को निर्यातकों और व्यापार तथा उद्योग से ऐसे विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें कहा गया है कि निर्यातकों के सीमा-शुल्क एजेंटों ने सीमा-शुल्क विभाग में पोतलदान बिल फाइल करते समय प्रतिफल वस्तु बॉक्स में असावधानी से “नहीं” पर निशान लगाया है। कई मामलों में निर्यात वस्तु के एमईआईएस हेतु पात्र होने के बावजूद “नहीं” पर निशान लगाया गया है, और इन पोतलदान बिलों को विदेश व्यापार महानिदेशालय के कम्प्यूटर सिस्टम पर भेजा नहीं गया है, इसलिए निर्यातक एमईआईएस के तहत दावा प्रस्तुत करने के लिए इन पोतलदान बिलों को कम्प्यूटर सिस्टम में प्राप्त करने/ढूँढ़ने में असमर्थ हैं। यह भी नोट किया गया है कि “हां” अथवा “नहीं” पर निशान लगाने की प्रणाली नई नहीं है और वर्ष 2012 से चालू है। चूंकि, विदेश व्यापार नीति (2015-20) की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.01 (छ) के तहत ईडीआई पोतलदान बिल के ब्यौरे की हाथ से प्रविष्टि की अनुमति नहीं है, अतः इन दावों को हाथ से भरा जाना संभव नहीं है।

2. विदेश व्यापार नीति (2015-20) की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.14 के अनुसार सभी निर्यातकों को पोतलदान बिलों की सभी श्रेणियों के तहत निर्यात पोतलदान फाइल करते समय एमईआईएस के तहत लाभ का दावा करने हेतु निम्नलिखित आशय की घोषणा करना अपेक्षित है :

“हमारा आशय भारत से पण्य निर्यात स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्रतिफल हेतु दावा करना है।”

दिनांक 01 जून, 2015 से आशय की घोषणा करना अनिवार्य है। सीबीईसी ने दिनांक 20 अप्रैल, 2015 को परिपत्र सं० 14/2015 भी जारी किया है जिसके तहत दिनांक 01.06.2015 से आशय की अनिवार्य रूप से घोषणा करना अपेक्षित है। ईडीआई द्वारा सृजित पोतलदान बिलों में निर्यातकों को “हां” पर निशान लगाना है, यदि वे एमईआईएस के तहत लाभ का दावा करना चाहते हैं और यदि वे एमईआईएस के तहत लाभ का दावा करना नहीं चाहते हैं, तो “नहीं” पर निशान लगाएं।

3. इन परिस्थितियों के आलोक में और मामले को सुलझाने के लिए विदेश व्यापार नीति 2015-20 की प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 3.14 के संदर्भ में पठित विदेश व्यापार नीति (2015-20) के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार 01.04.2015 से 31.05.2015 के बीच किए गए निर्यातों के मामलों में एतद्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाने की अनुमति देते हैं जहां पर निर्यातक ने ‘प्रतिफल मद बॉक्स’ में असावधानी से ‘नहीं’ चिह्नित किया है और एमईआईएस लाभ प्राप्त करना चाहते हैं :

(क) इन मामलों में निर्यातक आरए के पास आवेदन-पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करने के बाद आवेदन फाइल करते समय एमईआईएस प्रतिफलों के लिए मुक्त पोतलदान बिलों की वास्तविक प्रतियां प्रस्तुत करेंगे। आरए एफटीपी/एचबीपी के अन्य प्रावधानों के अनुसार ऐसे पोतलदान बिलों का निरीक्षण करने के बाद एमईआईएस प्रतिफल प्रदान करेंगे।

4. 01.06.2015 से, केवल उन्हीं पोतलदान बिलों पर एमईआईएस के तहत विचार किया जाएगा जो सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रेषित किए जाते हैं।

इस अधिसूचना का प्रभाव :

उन पोतलदान बिलों, जहां 01.04.2015 से 31.05.2015 के बीच किए गए निर्यातों के लिए सीमा-शुल्क विभाग में पोतलदान बिलों को फाइल करते समय आशय की घोषणा में 'प्रतिफल मद बॉक्स' में "हां" को चिह्नित न करके असावधानी से 'नहीं' दर्शाया गया है, को सीबीईसी से डीजीएफटी को प्रेषित किया जाएगा।

अनूप वधावन, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

Public Notice

New Delhi, the 9th October, 2015

No. 40/2015-2020

Subject: Declaration of intent under MEIS Scheme -reg.

F. No. 01/61/180/152/AM16/PC 3.— DGFT has received various representations from exporters and trade & Industry that many Custom House Agents of exporters have inadvertently ticked "N" in the reward item box while filing the shipping bills with Customs. Even though in many cases the item of export is eligible for MEIS, as "N" has been ticked, such shipping bills have not been transmitted to the DGFT system and exporters are therefore unable to obtain / find these shipping bills on the system for submitting claims under MEIS. It is also noted that the system of marking "Y" or "N" is not new and is in operation since 2012. Since para 3.01 (g) of Hand Book of Procedure to FTP (2015-20) does not allow manual feeding of EDI shipping bill details, filling of such claims is not possible manually.

2. As per para 3.14 of Hand Book of Procedure to FTP (2015-20), all exporters while filling export shipments under all categories of the shipping bills are required to declare the following intent to claim benefit under MEIS:

"We intend to claim rewards under Merchandise Exports from India Scheme (MEIS)".

Declaration of intent is mandatory with effect from June 1, 2015. CBEC has also issued a circular no. 14/2015 dated April 20, 2015, which requires mandatory declaration of intent from 1.6.2015 onwards. In EDI generated shipping bills, exporters are required to tick mark "Y" in case they intend to claim benefits under MEIS and "N" in case they do not intend to claim benefit under MEIS.

3. In light of these circumstances and to address the matter, in exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020) read with reference to para 3.14 of Handbook of Procedures of FTP 2015-20, the Director General of Foreign Trade hereby allows the following procedure to be followed where exports have been made between 1.4.2015 to 31.5.2015, and where the exporter has inadvertently marked "N" in the "reward item box" and wishes to seek MEIS benefits:

Exporters shall submit physical copies of free shipping bills after electronic filing of application to RA at the time of submission of application for MEIS rewards in these cases. RA shall grant MEIS rewards after examination of such shipping bills in accordance with other provisions of FTP/HBP.

4. From 01.06.2015, only those shipping bills, which are transmitted by Custom Authorities to DGFT, shall be considered under MEIS.

Effect of this Public Notice:

Shipping bills, where declaration of intent 'Y' has not been marked and 'N' has been ticked inadvertently in the 'reward item box' while filing shipping bill in Customs for exports made between 1.4.2015 to 31.5.2015, shall be transmitted by CBEC to DGFT.

ANUP WADHAWAN, Director General of Foreign Trade